

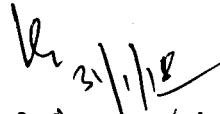
**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

दिनांक 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू की गयी कर प्रणाली के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में आ रही व्यापारियों की समस्याओं के दृष्टिगत कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० द्वारा यू०पी० वैट नियमावली के नियम 45 (7) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की समय-सीमा परिपत्र सं० विधि-4/परिपत्र भाग-3/2016-17/1106/1718044/वाणिज्य कर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ायी गयी । पुनः परिपत्र सं० विधि-4/परिपत्र भाग-5/2017-18/1774/1718076/ वाणिज्य कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा से वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि 31 जनवरी 2018 तक बढ़ायी गयी ।

जी०एस०टी० काउंसिल द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2018 से पूरे देश में एक साथ अन्तर्प्रान्तीय सम्व्यवहारों पर नेशनल ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया गया है । जी०एस०टी० से सम्बंधित कार्यों में व्यस्तता के कारण कुछ अधिवक्ता संगठनों द्वारा वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है । वेबसाइट पर उपलब्ध MIS के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिये दिनांक 31.01.2018 तक 167022 वार्षिक विवरणी दाखिल हुयी है, जो कुल एक्टिव व्यापारियों की संख्या 832037 के सापेक्ष 20.07 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2015-16 के लिये कुल 341400 वार्षिक विवरणी दाखिल हुयी थीं, जो कुल एक्टिव डीलर्स की संख्या 832885 के सापेक्ष 40.99 प्रतिशत रही है ।

उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 के लिये (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की तिथि अन्तिम रूप से दिनांक 28 फरवरी 2018 तक बढ़ायी जाती है ।

तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समस्त अधिवक्ता संघों तथा व्यापारिक संघों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।


(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।